गई थी । भुगतान संतुलन समस्या के कारण इसे बाद में घटाकर 150 करोड़ रुपये कर दिया गया था । इसके अलावा प्रयोक्ता उद्योगों द्वारा भी स्क्रैप का सीधे आयात किया जाता है ।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा इस्पात का उत्पादन

2644. **सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :**
डा. जितेन्द्र कुमार जैन :

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिसम्बर, 1991 तक भारतीय इस्पात प्राधिकरण का अपरिष्कृत इस्पात तथा विक्रय योग्य इस्पात का उत्पादन गत वर्ष के इन्हीं महीनों के दौरान हुए उत्पादन की तुलना में अधिक रहा है, और यदि हां, तो प्रत्येक उत्पाद के उत्पादन में कितनी-कितनी वृद्धि हुई है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उत्पादन में वृद्धि के बावजूद 1991-92 में इस्पात के निर्यात लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि इसका एक कारण अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय इस्पात का मूल्य अधिक होना है ; और

(घ) यदि हां, तो अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में इस्पात के मूल्यों को कम रखने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) जी, हां । "सेल" के अपरिष्कृत और विक्रय इस्पात के उत्पादन में, पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में, दिसम्बर, 1991 तक वृद्धि हुई है । इसका ब्यौरा निम्नानुसार है :—

(हजार टन)

	अप्रैल से दिसम्बर, 91 वास्तविक	अप्रैल से दिसम्बर, 90 वास्तविक	अन्तर मात्रा	अन्तर प्रतिशत
अपरिष्कृत इस्पात . .	7120	6301	819	13
विक्रय इस्पात . . .	5834	5208	626	12

(ख) और (ग) अंतर्राष्ट्रीय इस्पात व्यापार में मन्दी और विदेशी मांग में कमी की प्रवृत्ति के कारण निर्यात लक्ष्य पूरा नहीं किया जा सका।

(घ) इस्पात संयंत्रों द्वारा समय-समय पर लागत कम करने के विभिन्न उपाय किए जाते हैं । इन उपायों में क्षमता उपयोग में वृद्धि उत्पादकता में वृद्धि, तकनीकी आर्थिक निष्पादन में सुधार सहित ऊर्जा बचत, उन्नत अनुरक्षण और उपस्करों का आधुनिकीकरण शामिल है ।

अभी हाल में लोहे और इस्पात पर से नियंत्रण समाप्त किए जाने से भी इस्पात क्षेत्र में कार्य कुशलता और अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी जिससे लागत में कमी आयेगी ।

Production cost of Steel

2645. DR. YELAMANCHILI SIVA-JI: Will the Minister of STEEL be pleased to state:

(a) what is the cost of production of steel in different public sector units